भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2912**
उत्तर देने की तारीख **06** अगस्त**, 2025**

बीएसएनएल की प्रतिस्पर्धात्मकता

2912. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2007 से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बीएसएनएल को लाभप्रदता में वापस लाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय लागू किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार के पास बीएसएनएल की मोबिलिटी सेवाओं, फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) और लीज्ड लाइन सेवा में राजस्व वृद्धि का विस्तृत विवरण है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बीएसएनएल के 4जी और 5जी रोलआउट की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने बीएसएनएल के लिए ग्राहक संतुष्टि में सुधार और चर्न रेट को कम करने के लिए कोई पहल की है और और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं :

- वर्ष 2019 में, लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का पहला पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया गया जिससे बीएसएनएल/एमटीएनएल की परिचालन लागत में कमी आई।
- वर्ष 2022 में, लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया गया। इसमें नए पूंजी निवेश, ऋण पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- वर्ष 2023 में, सरकार ने लगभग 89 हजार करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से बीएसएनएल को 4जी/5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अनुमोदन प्रदान किया।
- इन पुनरुद्धार पैकेजों के अतिरिक्त, दिनांक 07.02.2025 को 6,982 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय कैपेक्स सहायता के लिए मंत्रिमंडल नोट के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इन पैकेजों के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से परिचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है ।

(ख) बीएसएनएल का मोबाइल राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 में 5,319 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 5,503 करोड़ रुपये हो गया है। बीएसएनएल का एफटीटीएच राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 में 2,652 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2,923 करोड़ रुपये हो गया है। बीएसएनएल का लीज्ड लाइन्स/ सर्किट राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 में 3,623 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3,658 करोड़ रुपये हो गया है।

(ग) और (घ) आत्मनिर्भर भारत पहल की तर्ज पर, बीएसएनएल ने अखिल भारतीय संस्थापना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 4जी साइटों के लिए क्रय आदेश जारी कर दिया है। 4जी उपकरणों की आपूर्ति सितंबर 2023 से शुरू हो गई है और दिनांक 30.06.2025 तक कुल 95,537 4जी साइट स्थापित की गई हैं और 90,035 साइट ऑन एयर हैं। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उपकरण का 5जी में उन्नयन किया जा सकता हैं ।

नेटवर्क अवसंरचना और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीएसएनएल सरकार की विभिन्न स्कीमें जैसे **4**जी सेचुरेशन स्कीम**,** बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)/ बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट (बीआईपी) आदि का निष्पादन कर रहा है। इन स्कीमों का विवरण https://usof.gov.in पर उपलब्ध है।

*****